

सं.जे - 11017/41/2011 - महात्मा गाँधी नरेगा (पार्ट)

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 07 जून, 2012

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
ग्रामीण विकास
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

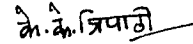
विषय : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गाँधी नरेगा) के अन्तर्गत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए दिनांक 10.05.2012 के दिशानिर्देशों में संशोधन ।

महोदय/महोदया,

राज्यों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की सहमति से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन/संयोजन/परिवर्तन किए हैं :

- (क) पैरा 5 (छ) [पृष्ठ 5]
 - (ख) पैरा 6.2 (ख) [पृष्ठ 6]
 - (ग) पैरा 7.1 (ख) [पृष्ठ 8]
 - (घ) पैरा 7.2 [पृष्ठ 9]
 - (ङ) पैरा 8 [पृष्ठ 9]
2. आवश्यक कार्रवाई के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है ।
 3. वित्त वर्ष 2012-13 के श्रम बजट में यदि शौचालयों को शामिल न किया गया हो तो यथोचित प्रक्रियाओं का अनुपालन करके आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं ।
 4. संदर्भ समझने में मदद करने के लिए संशोधनों/संयोजनों/परिवर्तनों को बड़े अक्षरों में दर्शाया गया है ।

भवदीय,



(डॉ.के.के. त्रिपाठी)

निदेशक (महात्मा गांधी नरेगा)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

1. मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव/ सचिव (ग्रामीण विकास) के प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव ।
2. संयुक्त सचिव (महात्मा गांधी नरेगा) के प्रधान निजी सचिव ।
3. महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग के सभी निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव ।

स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित
कार्यों को करने के
लिए दिशानिर्देश

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1
पैरा 1 ख (xv) के अन्तर्गत संशोधित
अनुदेश
(फाइल सं. जे - 11013/01/2011 महात्मा गांधी नरेगा (पार्ट VI), दिनांक :
07.06.2012)

महात्मा गाँधी नरेगा प्रभाग
ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

जून, 2012

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं०
1.	संदर्भ	3
2.	उद्देश्य	3
3.	लिए जा सकने वाले कार्यकलाप	4
4.	डिजाइन	4
5.	कार्य निष्पादन की वे मर्दे, जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता	4-6
6.	आयोजना और निष्पादन में महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं का अनुपालन	6-8
7.	व्यय का तरीका	8-9
8.	निगरानी एवं रिपोर्ट	9

संक्षिप्तियों की सूची

एएस/एफएस	प्रशासनिक/वित्तीय मंजूरी
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयक
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
यूनीक आईडी नंबर	विशिष्ट पहचान संख्या
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
जे.ईएन	कनिष्ठ अभियन्ता
महात्मा गाँधी नरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पीओ	कार्यक्रम अधिकारी
एसएलडब्ल्यूएम	ठोस एवं द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन
एसओआर	दरों की अनुसूची
टीए	तकनीकी सहायक
टीएस	तकनीकी मंजूरी
टीएससी	संपूर्ण स्वच्छता अभियान

नोट : स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिशानिर्देशों में पहला संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिनांक 10.05.2012 के परिपत्र पत्र सं. जे - 11013/01/2011 महात्मा गांधी नरेगा (पार्ट VI) द्वारा किया गया था। दिनांक 07.06.2012 के संशोधित परिपत्र में मौजूद दिशानिर्देशों के निम्नलिखित पैराग्राफ [पृष्ठ सं.] में संशोधन/संयोजन/परिवर्तन किए गए हैं :

- (क) पैरा 5 (छ) [पृष्ठ 5]
- (ख) पैरा 6.2 (ख) [पृष्ठ 6]
- (ग) पैरा 7.1 (ख) [पृष्ठ 8]
- (घ) पैरा 7.2 [पृष्ठ 9]
- (ङ) पैरा 8 [पृष्ठ 9]

महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 3(XV) के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यों की आयोजना, निष्पादन और निगरानी के लिए दिशानिर्देश/अनुदेश

1. सन्दर्भ :

1.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ.2265(स्था.) एवं का.आ. 2266 (स्था.) के तहत स्वच्छता-सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल करने के लिए मनरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 1(IX) के अंतर्गत कार्यों के दायरे का विस्तार किया था और इन कार्यों के लिए प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए थे। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, मनरेगा के अंतर्गत उप ढाँचा स्तर तक वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध है। इन दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई थी और इन्हें 10-05-2012 को संशोधित किया गया था। राज्यों द्वारा किए गए अनुरोधों और उपलब्ध कराई गई फीडबैक के आधार पर, यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 10-05-2012 के दिशानिर्देशों में किए गए कुछ प्रावधानों में आगे और संशोधन किया जाए।

1.2 दिनांक 10 मई, 2012 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के स्थान पर आगे दर्शाए गए संशोधित दिशानिर्देश लागू होंगे।

2. उद्देश्य :

स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने को शामिल करने के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

- (क) ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा इसके द्वारा ग्रामीण आजीविका के आधार को सुदृढ़ करना।
- (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्राम स्तर पर अवस्थापना सुविधा में सुधार लाना।
- (ग) महिलाओं को निजी और शालीन शौच सुविधाएं प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति बढ़ाना।

3. इन दिशानिर्देशों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत लिए जा सकने वाली गतिविधियाँ :

- (क) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित “ संपूर्ण स्वच्छता अभियान” के अनुदेशों/दिशा निर्देशों के अनुसार वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण । तथापि, आईएचएचएल के लिए मनरेगा से दी जाने वाली सहायता नीचे पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों तक ही सीमित होगी ।
- (ख) संस्थागत परियोजनाओं के रूप में आंगनवाड़ी शौचालय इकाई तथा विद्यालय शौचालय इकाई का निर्माण ।
- (ग) प्रस्तावित अथवा पूर्ण निर्मल ग्रामों में ठोस और तरल अपाशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) कार्य ।

4. डिजाइन और विशेषताएँ :

- (क) डिजाइनों और विशेषताओं के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा । भू-जलवायु स्थितियों और निर्माण सामग्री के आधार पर स्थानीय डिजाइन भिन्नताओं (रूपान्तरणों) में भी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।
- (ख) यदि एक लाभार्थी बेहतर डिजाइन/अधिक बड़े आकार के आईएचएचएल का निर्माण कराने का इच्छुक है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा । तथापि, मनरेगा से किया जाने वाला भुगतान इन दिशानिर्देशों के पैरा 7 में दिए गए प्रावधानों तक सीमित होगा ।

5. कार्य निष्पादन की वे मर्दें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता :

- (क) अकुशल कार्य के लिए केवल जॉब कार्ड धारक ही नियोजित किए जाएंगे । आईएचएचएल के लिए, यह आवश्यक है कि लाभार्थी भी अपने आईएचएचएल के निर्माण में कार्य करे । यदि लाभार्थी के पास जॉब कार्ड नहीं है तो वह इसके लिए आवेदन कर सकता है/आवेदन कर सकती है ।

- (ख) मस्टर रोलों का रखरखाव कार्यस्थल पर किया जाएगा, जिसकी प्रतियाँ ग्राम पंचायत में रखी जाएंगी। सभी डाटा पब्लिक डोमेन में भी होंगे तथा उनकी प्रविष्टि www.nrega.nic.in पर की जाएगी।
- (ग) मजदूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघर खातों के माध्यम से ही किया जाएगा, जब तक कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छूट न दी जाए।
- (घ) शौचालय इकाइयों के निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदार और मशीन को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
- (ङ) सृजित रोजगार का रिकार्ड अलग से रखा जाएगा।
- (च) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मामले में वैयक्तिक पारिवारिक लाभार्थी निजी भूमि/वासभूमि पर निर्माण कार्य के लिए मनरेगा के अंतर्गत पात्र परिवार होगा।
- (छ) जिला जल और स्वच्छता मिशन संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए अनुमोदित संपूर्ण स्वच्छता मिशन (टीएससी) योजना के बारे में ग्राम पंचायतों को सूचित करेगा। योजना में ग्राम पंचायत के लिए अनुमोदित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) की कुल संख्या शामिल होगी। ग्राम पंचायतें ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट संख्या के भीतर वैयक्तिक लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देंगी और इसको मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओं की अनुमोदित सूची के भाग के रूप में भी शामिल करेंगी।
- (ज) पैरा 3(क) और 3(ख) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण मनरेगा के अधीन केवल तभी शुरू किया जाएगा, जब कि इनका निर्माण संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत पहले नहीं किया गया है।
- (झ) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए समग्र आईएचएचएल इकाई को मनरेगा परियोजना माना जाएगा :
- (क) कार्य के लिए विशिष्ट पहचान (यूनीक आई.डी.) देना;
- (ख) निर्माण कार्य और सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि;
- (ग) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा;
- (घ) सतर्कता और निगरानी समिति द्वारा मूल्यांकन।

(ज) प्रत्येक ग्राम पंचायत सभी आईएचएचएल, विद्यालय शौचालय एवं आंगनवाडी शौचालय की एक संपूर्ण सूची रखेगी, चाहे शौचालयों का निर्माण कार्य मनरेगा में शामिल कार्यों के रूप में अथवा अन्य द्वारा पूरा किया गया हो। संपत्ति रजिस्टर में टीएससी से प्राप्त सहायता/प्रोत्साहन के उपयोग, राज्य प्रोत्साहन, लाभार्थी के अपने अंशदान तथा मनरेगा से प्राप्त राशि के व्यय का ब्यौरा अलग-अलग दर्शाया जाना चाहिए।

6. आयोजना और निष्पादन में महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रियाओं की सुनिश्चितता :

6.1 आयोजना :

(क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण करने के इच्छुक एक ग्राम/वार्ड अथवा ग्राम पंचायत के सभी पात्र लाभार्थियों की एक संयुक्त सूची तैयार की जाए। इस सूची को अनुमोदन और परियोजनाओं की सूची में शामिल करने के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सभी वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के लिए संयुक्त एस/एफएस जारी किए जाएंगे।

(ख) प्रत्येक संस्थागत परियोजना तथा एसएलडब्ल्यूएम कार्यों के लिए स्वीकृतियां अलग-अलग प्रदान की जाएंगी।

6.2 अनुमानित लागत :

(क) निर्माण कार्यों के लिए एस/एफएस देने के बाद पंचायत/संबंधित विभागों के सम्बद्ध तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता स्वच्छता सुविधाओं के लिए नक्शा/डिजाइन/विशिष्ट विवरण तथा क्षेत्र विशेष में मनरेगा कार्यों के लिए उपलब्ध एसओआर के अनुसार कार्यों की अनुमानित लागत तैयार करेंगे।

(ख) आईएचएचएल की अनुमानित लागत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की टाइप डिजाइन पर आधारित होंगे और संयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति (एस एण्ड एफएस) के अनुसार संयुक्त तकनीकी स्वीकृति (टीएस) जारी की जाएगी।

(ग) मनरेगा कार्यों के लिए प्रत्यायोजित मानदण्डों/शक्तियों के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी।

6.3 कार्य निष्पादन :

- (क) संबंधित ग्राम पंचायत कार्यान्वयन एजेंसी होंगी ।
- (ख) ग्राम पंचायत से अनुरोध प्राप्त होने पर, पीओ मस्टर रोल जारी करेगा ।
- (ग) प्रत्येक आईएचएचएल, विद्यालय शौचालय इकाई, आंगनवाड़ी शौचालय तथा एसएलडब्ल्यूएम परियोजना को स्वतंत्र कार्य माना जाएगा और तदनुसार मस्टर रोल जारी होंगे ।
- (घ) इन मस्टर रोलों के फार्मेट (रूप रेखा) में संशोधन ऐसा किया जाए, ताकि इस कार्य का प्रबंधन कुशलता से किया जा सके । तथापि, मनरेगा की अनुसूचियों में यथानिर्धारित न्यूनतम विशेषताओं को शामिल किया जाना आवश्यक होगा ।
- (ङ) उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावित संस्थागत शौचालयों के निर्माण के अतिरिक्त एक समय में एक ग्राम पंचायत में किये जाने वाले प्रस्तावित प्रत्येक 15-25 पारिवारिक शौचालयों (वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हुए) के लिए एक मेट की नियुक्ति की जाए ।
- i. उसे सौंपी गई ग्राम पंचायत/गांव/बस्ती में सभी वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों/संस्थागत परियोजनाओं के लिए मस्टर रोल का रखरखाव करना।
 - ii. कुशल और अकुशल मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करना।
 - iii. यह सुनिश्चित करना कि निर्माण कार्य कम-से-कम पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट डिजाइन के अनुरूप हो और इस आशय को प्रमाणित करेगा/करेगी।
 - iv. उसे सौंपे गए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य संपन्न होने पर मेट उपस्थिति और किए गए कार्य की मात्रा के संबंध में मस्टर रोल पर हस्ताक्षर करेगा/करेगी और अगली कार्रवाई के लिए कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक को सौंप देगा/देगी।
 - v. तत्पश्चात तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता ऐसी सभी इकाइयों के संबंध में एमबी दर्ज करेगा/करेगी।

- च) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण कार्य अकुशल मजदूरों की अधिकतम 20 दिहाड़ियाँ और कुशल मजदूरों (राजगीर/पलैम्बर) की 6 दिहाड़ियाँ लगाकर संपन्न किया जाना चाहिए। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को छोड़कर अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का कार्य मौजूदा एसओआर के अनुसार संपन्न किए जाएंगे।
- छ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों को छोड़कर अन्य स्वच्छता सुविधाओं के लिए मापन का कार्य साप्ताहिक आधार पर संबंधित तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता महात्मा गांधी नरेगा के मानकों के अनुसार करेंगे। मापन की प्रविष्टियाँ कार्य के आकलन के साथ मापन पुस्तिका एवं मस्टर रोल में दर्ज की जाएंगी। वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के मामले में, शौचालय तैयार हो जाने पर कार्य का मापन किया जाएगा।
- ज) संपूर्ण स्वच्छता अभियान दल की मदद से ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, आंगनवाड़ी शौचालय और स्कूल शौचालय के निर्माण में सभी कार्यकलापों और सामग्री की आपूर्ति का आयोजन और निष्पादन इस प्रकार किए जाएं ताकि कार्य के संपादन एवं निष्पादन में निरंतरता बनी रहे।

7. व्यय का तरीका :

7.1 स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों पर व्यय की पूर्ति महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से और महात्मा गांधी नरेगा प्रक्रिया के अनुसार मस्टर रोलों के जरिए की जाएगी :

- क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण कार्य के लिए अकुशल मजदूर (अधिकतम 20 दिहाड़ियाँ) और कुशल मजदूर (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सामग्री घटक के अंतर्गत अधिकतम 6 दिहाड़ियाँ)। तथापि, महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत दर्ज की जाने वाली राशि प्रति शौचालय 4500 रुपए से अधिक नहीं होगी।
- ख) कुशल मजदूर और मेट उपलब्ध कराने की लागत महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधान के अनुसार सामग्री घटक के तहत दर्ज की जाएगी और तदनुसार इस लागत को निर्माणाधीन वैयक्तिक शौचालयों में आनुपातिक आधार पर बाँटा जाएगा।

7.2 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए किए जाने वाले शेष आवश्यक कार्यकलापों का वित्तपोषण पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन/राज्य सरकार या लाभार्थी के अपने अंशदान का उपयोग करते हुए संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम से किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ जिला जल स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) यथानिर्धारित कार्य करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य, दोनों के अंशदान रिलीज करेगा, ताकि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए निर्धारित लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

7.3 तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्यों का मापन, निर्धारित टास्क के आधार पर कार्य का आकलन किए जाने एवं मस्टर रोल एवं मापन पुस्तिका में विधिवत दर्ज किए जाने के बाद ही महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले अकुशल एवं कुशल मजदूरों को भुगतान किया जाएगा।

8. निगरानी और रिपोर्ट :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) और संबंधित दिशानिर्देशों में यथोल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण स्वच्छता अभियान चला रही एजेंसी की होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण कार्य की सामाजिक लेखा परीक्षा महात्मा गांधी नरेगा और संपूर्ण स्वच्छता अभियान के विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की ऑनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के आईएमआईएस में उपयुक्त फार्मेट विकसित करके निर्मित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों और संपूर्ण स्वच्छता अभियान एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करते हुए तालमेल के जरिए किए गए खर्च की रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त निगरानी व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के बारे में दो अलग-अलग रिपोर्टें तैयार न हों। मासिक आधार पर ग्राम पंचायत-वार आंकड़ों का संकलन कर जिला कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से रिपोर्टें भेजी जाएंगी।

ये दिशानिर्देश पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सहमति से जारी किए गए हैं।

क. के. त्रिपाठी
(डा. के. के. त्रिपाठी)
निदेशक (महात्मा गांधी नरेगा)